



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]
No. 32]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 12, 1967 (श्रावण 21, 1889)

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 12, 1967 (SRAVANA 21, 1889)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 25 जुलाई, 1967 तक प्रकाशित किये गये :—
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 25th July, 1967:—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
90	No. 57—ITC(PN)/67 dated 3rd July, 1967.	Ministry of Commerce	Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1967.
91	No. 58—ITC(PN)/67 dated 7th July, 1967. No. 59—ITC(PN)/67, dated 7th July, 1967.	Do. Do.	Import Policy for Registered Exporters for Chemicals for the year April 1967—March, 1968. Terms and conditions governing the issuance of licences for private sector imports from West Germany Under West German Credit.
92	No. 60—ITC(PN)/67 dated 10th July, 1967.	Do.	Submission of consolidated applications for raw materials, components and spares by small scale units and non—SSI units sponsored by the state Directors of Industries during April, 1967—March 1968.
93	No. 61—ITC(PN)/67, dated 12th July, 1967. No. 62—ITC(PN)/67 dated 12th July, 1967.	Do. Do.	Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1967. Amendment to the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1967 (Amendment No. 2).
94	No. 63—ITC(PN)/67 dated 14th July, 1967. No. 64—ITC(PN)/67 dated 14th July, 1967.	Do. Do.	Dutch General purpose Credit—Licensing conditions applicable thereunder for private sector imports. Acceptance of Treasury Challans—Import Licence application fees.
95	No. DUR—2(4)/66, dated 19th July, 1967.	Min. of Steel Mines & Metals	Recommendations of a one-man Committee of Shri G. Pande, ex-Vice Chancellor, Roorkee University regarding the problem Durgapur Steel Plant.
101	No. 65—ITC(PN)/67, dated 25th July, 1967.	Ministry of Commerce	Import Policy for the year April 1967— March, 1968.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंचाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)		पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	687	भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	781

	पृष्ठ (Pages)		पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	169
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	603	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	569
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	355
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	133
भाग II—खंड 3—उप खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1293	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	369
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2755	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	131
		पूरक सं० 32—	
		5 अगस्त 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1321
		15 जुलाई 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1333
<hr/>			
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	687	PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2755
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	781	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	169
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	569
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	603	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	355
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	133
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	369
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1293	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	131
		SUPPLEMENT No. 32—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 5th August 1967	1321
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 15th July 1967—	1333

भाग I—खण्ड 1 PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1967

शुद्धिपत्र

सं० 63-प्रेज०/67—दिनांक 1 जनवरी 1966 के भारतीय राजपत्र के भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 127-प्रेज०/65, दिनांक 16 अक्तूबर 1965 में शुद्धि करने हेतु :—

पृष्ठ 12 पर क्रम संख्या 1 में

बास्ते "पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 सितम्बर 1965".

पढ़ें "पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 सितम्बर 1965"।

सं० 64-प्रेज०/67—दिनांक 1 जनवरी 1966 के भारतीय राजपत्र के भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 129-प्रेज०/65, दिनांक 11 नवम्बर 1965 में शुद्धि करने हेतु :—

पृष्ठ 15 पर

(क) क्रम संख्या 1 में

बास्ते "पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 सितम्बर 1965".

पढ़ें "पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 अगस्त 1965"।

(ख) क्रम संख्या 2 में

बास्ते "पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 सितम्बर 1965".

पढ़ें "पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 अगस्त 1965"।

सं० 65-प्रेज०/67—दिनांक 1 जनवरी 1966 के भारतीय राजपत्र के भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 134-प्रेज०/65, दिनांक 16 अक्तूबर 1965 में शुद्धि करने हेतु :—

पृष्ठ 14 पर क्रम संख्या 6 में

बास्ते "पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 सितम्बर 1965".

पढ़ें "पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 सितम्बर 1965"।

ब० जे० मोर, राष्ट्रपति के उप-सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 28 जुलाई 1967

संकल्प

सं० 258/4/67-ए०वी०डी०—भारत सरकार द्वारा यह निश्चय किया गया है कि पुलिस अनुसंधान सलाहकार परिषद्

से सम्बन्धित गृह मंत्रालय संकल्प संख्या 242/110/65-ए०वी०डी० दिनांक 7 नवम्बर, 1966 में, अनुच्छेद 2 के अधीन टिप्पणी 3 की धारा (एफ०) के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी :—

“(ज) सामाजिक कार्य के भारतीय सम्मेलन अथवा किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान एकक के प्रतिनिधि पुलिस अनुसंधान के किसी क्षेत्र में सम्बन्धित तकनीकी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ।”

आदेश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को भेजी जाये। यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिये भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

(हस्त:) अपठनीय
संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1967

सं० 10-7/67-एफ० ए० आई० टी०—राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन सम्पर्क समिति, जो खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के प्रस्ताव संख्या एफ-10-1/65-एफ० ए० आई० टी० दिनांक 9 सितम्बर 1966 के अनुसार पुनर्गठित हुई थी, में प्रतिनिधित्व करने के लिये लोक सभा के अधोलिखित सदस्यों को 12 जून 1970 तक तीन वर्षों के लिये निर्वाचित किया गया है:

1. श्री विनय कृष्ण दास चौधरी।
2. श्री अवदेश चन्द्र सिंह।
3. चौधरी नीतिराज सिंह।
4. श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव।

ग० का० कसबकर, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1967

ग० 30-24/67-भूमि संरक्षण (योजना)—राष्ट्रपति जी, डा० आर पी० धीर की, जो कि अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली से संलग्न वैज्ञानिकों के पूल के एक अधिकारी हैं, अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन के कलकत्ता शाखा में 24 जून 1967 के पूर्वाज्ञ

से आगामी आदेशों तक भूमि रसायनज्ञ के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करने हैं।

बी० एम० निगम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1967

संकल्प

सं० 6-6/67-सामान्य-2—शीघ्रता से विकसित होने वाली अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के कार्य की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के समस्त ढाँचे की परीक्षा के विचार से, भारत सरकार ने खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) में संसद्-सदस्यों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का निश्चय किया है।

2. समिति का गठन निम्न होगा :—

अध्यक्ष

1 श्री आनन्द नारायण मुल्ला, संसद् सदस्य (लोक सभा)

सदस्यगण

2. श्री लीलाधर कोटोकी, संसद् सदस्य (लोक सभा)
3. श्री शीलभद्रा याजी, संसद् सदस्य (राज्य सभा)
4. श्री रणधीर सिंह, संसद् सदस्य (लोक सभा)
5. श्री ओंकारलाल बोहरा, संसद् सदस्य (लोक सभा)
6. श्री नरेन्द्र सिंह महिदा, संसद् सदस्य (लोक सभा)
7. श्री बी० शंकरानन्द, संसद् सदस्य (लोक सभा)
8. चौ० ब्रह्म प्रकाश, संसद् सदस्य (लोक सभा)
9. डा० महदेव प्रसाद, संसद् सदस्य (लोक सभा)
10. श्रीमती शारदा मुकजी, संसद् सदस्य (लोक सभा)
11. श्री अतूप सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा)
12. प्रोफेसर एन० जी० रंगा, संसद् सदस्य (लोक सभा)
13. श्री कंवर लाल गुप्ता, संसद् सदस्य (लोक सभा)
14. श्री बी० कृष्णामूर्ति, संसद् सदस्य (लोक सभा)
15. श्री ए० श्रीधर, संसद् सदस्य (लोक सभा)
16. श्री ए० डी० मेनी, संसद् सदस्य (राज्य सभा)
17. श्री त्रिलोकी सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा)
18. श्री ए० पी० चटर्जी, संसद् सदस्य (राज्य सभा)
19. डा० जेड० ए० अहमद, संसद् सदस्य (राज्य सभा)
20. श्री विजय कुमार त्रिवेदी—एम० एल० ए०
श्रीमती सोयायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9
21. श्री एम० बी० राजागव, एम० एल० ए०, आन्ध्र प्रदेश
22. श्री उदित नारायण शर्मा, राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ
23. श्री डी० एम० देसाई, राजस्व मंत्री, महाराष्ट्र सरकार,
बम्बई
24. श्री के० एम० सिवा सुब्रामानियम्, सचिव, राजस्व विभाग,
मद्रास सरकार, मद्रास
25. पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधि (नामजद होना है)।

3. **विचारार्थ विषय** : यह समिति भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत लोक सेवा के लिए और सार्वजनिक तथा निर्जी प्रक्षेत्रों में कम्पनियों के लिए भूमि अर्जन योजना का निम्न विशेष संदर्भों में परीक्षण करेगी :

- (1) लोक सेवा के लिए भूमि अर्जन का नियमित करने वाले सिद्धान्त
- (2) सुआवजा के निर्णय के सिद्धान्त
- (3) प्रशासनिक देरी के कारण और उनको हटाने के उपाय
- (4) बेदखल हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकारी उत्तरदायित्व की सीमा और इस उत्तरदायित्व को निभाने से सम्बन्धित सिफारिशें
- (5) भूमि अर्जन पर एकसमान केन्द्रीय कानून बनाने की सम्भाव्यता, जो कि समस्त देश में लागू हो सके, यद्यपि "भूमि अर्जन" कार्य संवर्ती-सूची में है।

4. समिति के सदस्यगण अवैतनिक होंगे, लेकिन गैर-सरकारी सदस्यों को वित्त मन्त्रालय के कार्यालय-जापन संख्या 6/26/ई-4/59, दिनांक 5-9-1960 के अनुसार जो समय-समय पर संशोधित होता रहा है, यात्रा-भत्ता और दैनिक-भत्ता मिलेगा। सरकारी अधिकारियों को जोकि इस समिति के सदस्य हैं, यात्रा-भत्ता और दैनिक-भत्ता सामान्य रूप से लागू होने वाले नियमों के अनुसार मिलेगा।

5. इस समिति की बैठक उस समय बुलाई जायेगी, जब भी इसकी आवश्यकता समझी जायेगी। समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा, परन्तु यह समिति उन अन्य स्थानों का दौरा भी कर सकती है, जहाँ जाना आवश्यक समझी और उन अन्य स्थानों पर अपनी बैठक कर सकेगी, जहाँ पर आवश्यक हो।

6. समिति कार्य करने की अपनी विधि विकसित करेगी।

7. यह समिति भारत सरकार को यथा-सम्भव शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन 31-3-68 से पहले ही रिपोर्ट दे देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के समस्त सदस्यों, भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों/विभागों, प्रधान-मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रीमण्डल सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, समस्त राज्यों और संघ क्षेत्रों के राजस्व सचिवों, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (कृषि विभाग) के समस्त सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद् पुस्तकालय (5 प्रतियाँ) और समस्त राज्यों और संघ क्षेत्रों को भेज दी जाये।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी० सिवरासन, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1967

सं० 5-24/66-सी० सी० 1—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के कृषि विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, तम्बाकू विकास, मद्रास के उप-निदेशक, डा० जी०

जे० पटेल की सेवायें कृषि मंत्रालय, आनन्द (गुजरात राज्य) को सौंप दी गई हैं। उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय को 15 जून 1967 के पूर्वाह्न से कार्यभार में मुक्त कर दिया गया था।

आई० पी० माथुर, उप-मन्त्रि

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 1967

संस्थाप

सं० 8-3/67-ए० एम० 4—श्री जे० एम० शर्मा, कृषि विभाग के अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार को देश भर के कृषि प्रदर्शनों की प्रगति तथा परिणामों का परीक्षण तथा समन्वय करने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति का पुनर्निर्माण खाद्य, कृषि, सामुदायिक विभास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के संस्थाप संख्या 8-3/67-ए० एम० 4, दिनांक 27 मई 1967 के अन्तर्गत हुई थी।

आदेश

आदेश है कि इस संस्थाप को भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आदेश है कि इस संस्थाप की मचना सब सम्बन्धित व्यक्तियों को दी जाए।

बी० पी० पाल, अवग मन्त्रि
तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1967

सं० ई० 67 सी० ओ० 1/66/आर० बी० 1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 3-7-67 की अधिसूचना सं० ई० 67 सी० ओ० बी 1/66/आर 1 में आशिक आणोघन करने हुए भारत सरकार ने उत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक, श्री टी० एस० पार्थ-सारथी को जो इन समय रेलवे बोर्ड में विशेष-कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त है, श्री के० एन० कृष्णन्, निदेशक, रेल समन्वय, रेलवे बोर्ड की अगह, "रेलवे खानपान और यात्री सुविधा समिति, 1967" का सदस्य-मन्त्रि नियुक्त करने का विनिश्चय किया है।

सी० एम० परमेश्वरन्, सचिव,
रेलवे बोर्ड

सिचाई व बिजली, मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 1967

संक्षेप

सं० ई० एम०-2-28(7)/67—यह निर्णय किया गया है कि चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में दिल्ली के निकट बदरपुर में एक ताप बिजलीघर का निर्माण किया जाए जिसके आरम्भ में 100-100 मेगावाट के तीन यूनिट हों। बदरपुर ताप बिजलीघर की सुदक्ष, मितव्ययी और शीघ्र कार्यान्विति को सुनिश्चित करने के विचार से भारत सरकार ने एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है जो इस परियोजना के समस्त कार्यभार को, भारत सरकार, सिचाई व बिजली मंत्रालय की सामान्य निगरानी में, तकनीकी व वित्तीय पक्षों सहित संभालेगा। निर्माण का वार्षिक कार्य नियंत्रण बोर्ड के निदेशन में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा किया जाएगा

जिसके आधीन इस उद्देश्य के लिए एक पृथक निर्माण यूनिट स्थापित किया जाएगा।

2 मुख्य अभियन्ता (अथवा परियोजना प्रबन्धक), बदरपुर ताप बिजलीघर परियोजना को तथा संबंध रखने वाले अन्य अधिकारियों को नियंत्रण बोर्ड के निदेश पर कार्य, पूर्णियों और सेवाओं के लिए ठेका देने के अधिकार सौंप जाएंगे। इन ठेकों के कार्यान्विति भारत सरकार के नाम पर की जाएगी।

3. बदरपुर ताप परियोजना नियंत्रण बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- | | |
|---|---------|
| (1) सिचाई व बिजली मंत्री | अध्यक्ष |
| (2) सचिव, सिचाई व बिजली मंत्रालय | सदस्य |
| (3) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय,
(व्यय विभाग, सिचाई व बिजली) | |
| अथवा उसका प्रतिनिधि | सदस्य |
| (4) सचिव, जनकार्य विभाग, हरियाणा सरकार | सदस्य |
| (5) सचिव, सिचाई व बिजली विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार | सदस्य |
| (6) सचिव, योजना और विकास, बिजली प्रशासन | सदस्य |
| (7) निदेशक (विदेशी मुद्रा व बिजली), सिचाई व बिजली मंत्रालय | सदस्य |
| (8) उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग | सदस्य |
| (9) सदस्य, (ताप), केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (जल स्कंध) | सदस्य |
| (10) मुख्य अभियन्ता (अथवा परियोजना प्रबन्धक), बदरपुर ताप परियोजना | सदस्य |

4. (क) बोर्ड का कार्यालय दिल्ली में होगा।

(ख) बोर्ड की सहायता के लिए एक पूर्णकालिक सचिव, एक वित्तीय सलाहकार और आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारी होंगे। सचिव, वित्तीय सलाहकार और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति सिचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

(ग) जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, बोर्ड बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में अन्य अधिकारियों को जिन्हें वह उचित समझे, आमंत्रित कर सकता है। किसी उद्देश्य के लिए यदि उपसमिति की नियुक्ति आवश्यक समझी गई, तो इसे उपसमिति नियुक्त करने का भी अधिकार होगा।

5. विशेषाविशेष रूप से और उपर्युक्त उपबन्धों की व्यापकता के प्रतिकूल न जाते हुए बदरपुर ताप परियोजना नियंत्रण बोर्ड—

- (1) परियोजना के प्राक्कलन की जांच करेगा, आवश्यक मंशोधनों के बारे में सलाह देगा, और भारत सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उस प्राक्कलन को भेजेगा;
- (2) अभिकल्प तैयार करने और विशेषज्ञों की सलाह देने के सभी प्रस्तावों की जांच करेगा और निर्णय देगा;
- (3) मुख्य अभियन्ता (अथवा परियोजना प्रबन्धक) और इस परियोजना की कार्यान्विति में संबंध रखने वाले अन्य अधिकारियों को परियोजना की सूचारू कार्यान्विति के लिए आवश्यक समझे गए तकनीकी व वित्तीय दोनों प्रकार के अधिकार सौंपने के बारे में समय-समय पर जांच करेगा और उनकी स्वीकृति देगा;

- (4) इस परियोजना की कार्यान्विति निविद्ध तथा सुचारु ढंग से हो, इस विचार में विविध प्रकार के कामों के लिए विभिन्नियों तथा दर अनुसूतियों की जांच करेगा और यथावश्यक उन्हें निर्धारित करेगा;
- (5) उन सभी छोटे प्राकल्पों और ठेका के लिए स्वीकृति देगा जिन की लागत परियोजना के मुख्य अभियन्ता (अथवा परियोजना प्रबन्धक) को दी गई शक्तियों से बाहर होगी ;
- (6) ठेके पर काम देने और पूर्ति आदेश देने के उन सभी प्रस्तावों की स्वीकृति देगा जो कि परियोजना के मुख्य अभियन्ता (अथवा परियोजना प्रबन्धक) की शक्तियों से बाहर होंगे ;
- (7) अपने काम काज का चलान के लिए अधिकार समर्पण और प्रक्रिया संबंधी नियम बनाएगा ;
- (8) उपलब्ध धन राशियों, परियोजना के वित्तीय पक्ष और परिणामों की शीघ्र प्राप्ति की वाछनीयता का ध्यान में रखते हुए, परियोजना के विभिन्न भागों के लिए निर्माण कार्यक्रम निर्धारित करेगा ;
- (9) मुख्य अभियन्ता (अथवा परियोजना प्रबन्धक) तथा अन्य अधिकारियों से निर्धारित फार्म में कार्यों और व्यय के संबंध में प्रगति रिपोर्ट मगाएगा, परियोजना के विभिन्न युनिटों की प्रगति का अवलोकन करेगा और कार्य को शीघ्र पूरा करने के उपाय बनाएगा ; और
- (10) परियोजना अधिकारियों के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और उपयुक्त आनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश करेगा ।

6. बोर्ड की एक स्थायी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- | | |
|---|---------|
| (1) सचिव, मिचार्डी व बिजली मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (2) सदस्य (ताप), केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (जल रक्षक) | सदस्य |
| (3) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) | सदस्य |
| (4) निदेशक (विदेशी मुद्रा व बिजली) मिचार्डी व बिजली मंत्रालय | सदस्य |
| (5) मुख्य अभियन्ता (अथवा परियोजना प्रबंधक), बदरपुर ताप परियोजना | सदस्य |
| (6) वित्त सलाहकार, बदरपुर ताप परियोजना | सदस्य |
| (7) सचिव, बदरपुर ताप परियोजना नियंत्रण बोर्ड | सचिव |

7. बोर्ड स्थायी समिति को, जैसे भी उचित समझे, अपने कार्य और अधिकार सौंप सकता है ।

8. स्थायी समिति बोर्ड की ओर से उन तकनीकी, वित्तीय और आम मामलों पर फैसला करेगी जो बोर्ड द्वारा उस को सौंपे गए हों ।

9. बोर्ड द्वारा सौंपे गए मामलों पर स्थायी समिति के फैसलों का गारांश बोर्ड की सृचना के लिए उसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

10. स्थायी समिति काम-काज के नियम बनाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और दिल्ली प्रशासन को भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राज-पत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

दिनांक 17 जुलाई 1967

संकल्प

सं० ई० एल०-2-24(2)/67—सिचार्डी व बिजली मंत्रालय ने ग्राम विद्युतन की गति को बढ़ाने के विचार से अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सहायता से भारत में ग्राम बिजली सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने की संभाव्यता के संबंध में 1966 में एक अनुसंधान कार्य का प्रायोजन किया था जो अमरीका के राष्ट्रीय ग्राम बिजली सहकारी संघ द्वारा किया जाना था । इस कार्यक्रम के अनुसार भारत में एक विशेषज्ञ दल आया और इसने सम्बद्ध राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रकमों के संबंध में अध्ययन और विस्तृत स्थल अनुसंधान करने के पश्चात् इस कार्य के प्रथम चरण की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे भारत सरकार ने सिद्धान्त रूप से मान लिया है । इस रिपोर्ट (चरण-1) की एक सिफारिश यह है कि भारत सरकार एतदर्थ आधार पर एक समिति अथवा पैनल स्थापित करे ।

2. इस दल द्वारा की गई इस सिफारिश की परिपालना में एतदर्थ आधार पर एक समिति स्थापित की गई है जिसकी बनावट और कार्य निम्नलिखित होंगे :—

बनावट

अध्यक्ष

- (1) सचिव, मिचार्डी व बिजली मंत्रालय

सदस्य

- (2) आयुक्त (सहकारिता) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास व सहकारिता मंत्रालय (सहकारिता विभाग) ;
- (3) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)—योजना वित्त प्रभाग ;
- (4) प्रधान (बिजली), योजना आयोग ;
- (5) आयुक्त, औद्योगिक सहकारी संस्थाएं, औद्योगिक विकास व कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ;
- (6) श्री वी० कुरिन, महाप्रबंधक, कायरा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, आनन्द ।

कार्य

यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :

- (1) विभिन्न संबद्ध सरकारी विभागों से कार्य का समन्वय करना;
- (2) आवश्यक पूजी का प्रबंध करना;
- (3) इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन करना व निदेश देना तथा प्रायोगिक परियोजनाओं को आरम्भ करवाने में सामन्वय: सहायता करना।

3 उपर्युक्त समिति के सचिव व उप-सचिव के रूप में काम करने तथा प्रायोगिक परियोजनाओं और अन्य संबद्ध अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं :

- | | | |
|---|---|--------------|
| (1) श्री एम० के० बन्सल, निदेशक,
योजना व प्रगति निदेशालय,
केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग
(विजली स्कंध)। | } | सचिव |
| (2) श्री एच० प्रसाद, अवर सचिव,
सहकारिता विभाग, खाद्य, कृषि,
सामुदायिक विकास व सहकारिता
मंत्रालय। | } | संयुक्त सचिव |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को संबद्ध सदस्यों, राज्य सरकारों, राज्य विजली बोर्डों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पाम भेज दिया जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० पी० मथानी, सचिव

श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय**(श्रम और रोजगार विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1967

सं० ई० एन्ड पी० 4/1/36/66—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(ए) के अनुसार, भारत सरकार एन्ड द्वारा शा० एम० टी० मिरानी, सह सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय को, श्री पी० एम० नायक, अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्थान पर, जो कि डेप्युटेशन पर विदेश जा रहे हैं, 31 जुलाई, 1967 से उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है।

2. तदनुसार 20 दिसम्बर, 1958/अप्रहायण 29, 1880 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई० एन्ड पी० 4(24)/58, तारीख 12 दिसम्बर, 1958 (समय समय पर संशोधित) में निर्दिष्ट प्रविष्टि

"1—श्री पी० एम० नायक,	भारत सरकार
अपर सचिव,	द्वारा
श्रम और रोजगार मंत्रालय	नामित"
नई दिल्ली।	

के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जायगा

"1—शा० एम० टी० मिरानी,	भारत सरकार
सह सचिव,	द्वारा
श्रम और रोजगार मंत्रालय,	नामित।"
नई दिल्ली।	

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**RESOLUTION**

New Delhi, the 29th July 1967

No. 14/3/66-SCT.II.—Shri N. Sundaram, Director General, Backward Classes Welfare, Department of Social Welfare, has ceased to be Member-Secretary to the Committee on Untouchability, Economic Uplift and Educational Development of Scheduled Castes, with effect from 7th July, 1967.

ORDER

ORDERED that the above be published in the Gazette of India for general information.

MIR NASRULLAH, Dy. Secy

MINISTRY OF COMMERCE**RESOLUTIONS**

New Delhi, the 13th July 1967

No. 20/1/64-HC.—The Government of India have decided to extend, up to the 15th August, 1967, the term of office of Members of the All India Handicrafts Board, as reconstituted in this Ministry's Resolution No. 20(1)/64-Handicrafts, dated the 28th December, 1964, read with Resolutions of the same number dated the 31st December, 1964, 11th March, 1965, 6th May, 1965 and Resolution No. 20(1)/64-HC, dated the 30th December 1966

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

The 29th July 1967

No. 19/6/66-KVI(P).—In partial modification of the Govt. of India in the Ministry of Commerce Resolution No. 19/6/66-KVI(P), dated the 8th June, 1966, as amended vide Resolutions No. 19/6/66-KVI(P), dated the 12th August, 1966, 4th Oct., 1966 and the 5th April, 1967, the Government of India have decided, in view of the volume of work involved and the progress made so far, to extend by five months the period for submission of the Report by the Khadi & Village Industries Committee. The following may, therefore, be substituted for paragraph 4 of the Govt. of India Resolution No. 19/6/66-KVI(P), dated the 8th June, 1966, as amended :—

"4. The Committee is requested to submit its Report to Government by the 31st December, 1967."

2. ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information and that it be communicated to all.

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Deptt. of Agriculture)

New Delhi the 22nd July 1967

No. 10-7/67-FAIT.—The following members of the Lok Sabha have been elected to serve as members of the National Food & Agriculture Organisation Liaison Committee in accordance with the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) Resolution No. 10-1/65-FAIT, dated the 9th September, 1966 as amended to date, for a period of three years ending 12th June, 1970 :—

1. Shri Benoy Krishna Daschowdhury.
2. Shri Awadesh Chandra Singh.
3. Chaudhary Nitiraj Singh.
4. Shri Nagendra Prasad Yadav.

G. K. KASBEKAR, Dy Secy

New Delhi, the 24th July 1967

No. 30-24/67-Soil Cons.(Pl).—The President is pleased to appoint Dr. R. P. Dhir, an Officer of the Scientists Pool, attached to the All India Soil and Land Use Survey Organisation, New Delhi, as Soil Chemist at the Red and Laterite Soils Region I, Calcutta under the All India Soil and Land Use Survey Organisation, in a temporary capacity with effect from the forenoon of 24th June, 1967, until further orders.

V. S. NIGAM, Under Secy

RESOLUTION

New Delhi, the 27th July 1967

No. 6-6/67-Gen.II.—In the context of a rapidly developing economy, a review of the working of the Land Acquisition Act, 1894 has become necessary. With a view to examining the entire framework of the Land Acquisition Act, 1894 the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) have decided to set up a Committee consisting of members of Parliament and representatives of State Governments.

2. The composition of the Committee will be as follows : —

Chairman

- (i) Shri Anand Narain Mulla, M.P. (Lok Sabha)

Members

- (ii) Shri Liladhar Kotoki, M.P. (Lok Sabha)
- (iii) Shri Sheelbhadra Yajee, M.P. (Rajya Sabha)
- (iv) Shri Randhir Singh, M.P. (Lok Sabha)
- (v) Shri Onkarlal Bohra, M.P. (Lok Sabha)
- (vi) Shri Narendra Singh Mahida, M.P. (Lok Sabha)
- (vii) Shri B. Shankaranand, M.P. (Lok Sabha)
- (viii) Ch. Brahm Parkash, M.P. (Lok Sabha)
- (ix) Dr. Mahadev Prasad, M.P. (Lok Sabha)
- (x) Smt. Sharda Mukherjee, M.P. (Lok Sabha)
- (xi) Shri Anup Singh, M.P. (Rajya Sabha)
- (xii) Prof. N. G. Ranga, M.P. (Lok Sabha)
- (xiii) Shri Kanwarlal Gupta, M.P. (Lok Sabha)
- (xiv) Shri V. Krishnamurthy, M.P. (Lok Sabha)
- (xv) Shri A. Sreedharan, M.P. (Lok Sabha)
- (xvi) Shri A. D. Mani, M.P. (Rajya Sabha)
- (xvii) Shri Triloki Singh, M.P. (Rajya Sabha)
- (xviii) Shri A. P. Chatterjee, M.P. (Rajya Sabha)
- (xix) Dr. Z. A. Ahmed, M.P. (Rajya Sabha)
- (xx) Shri Vijaykumar Trivedi, M.L.A., Shrimali Society, Navrangpura, Ahmedabad-9.
- (xxi) Shri M. B. Raja Rao, M.L.A., Andhra Pradesh.
- (xxii) Shri Udit Narain Sharma, Revenue Minister, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

(xxiii) Shri D. S. Desai, Minister for Revenue, Government of Maharashtra, Bombay.

(xxiv) Shri K. S. Sivasubramanian, Secretary, Revenue Department, Government of Madras, Madras.

(xxv) Representative of West Bengal Government (to be nominated).

3. *The terms of reference* : The Committee will examine the scheme of acquisition of land for public purpose and for companies in the public and private sectors under the Land Acquisition Act, 1894, with particular reference to :—

- (i) principles which should govern acquisition of land for a public purpose;
- (ii) principles for determining compensation;
- (iii) reasons for administrative delays and remedial measures;
- (iv) extent of Government responsibility for rehabilitation of evicted families and recommendations about discharge of this responsibility;
- (v) feasibility of enacting a uniform Central law on 'land acquisition' which may be applicable to the whole country although 'land acquisition' is in the Concurrent List.

4. The membership of the Committee will be honorary, but non-official members will be entitled to travelling and daily allowances in accordance with the orders contained in the Ministry of Finance's Office Memorandum No. 6/26/E-IV/59, dated the 5th September, 1960, as amended from time to time. Government officials who are members will be governed in the matter of T.A. and D.A. by the rules normally applicable to them.

5. The Committee will meet as often as considered necessary. The headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may visit such other places as it deems fit for gathering evidence on the field and hold its meetings at such other places as it considers necessary.

6. The Committee will evolve its own procedure of work.

7. The Committee will submit its report to the Government as early as possible, but not later than 31st March, 1968.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Members of the Committee, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Revenue Secretaries in all States and Union Territories, all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library (5 copies) and all State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. SIVARAMAN, Secy

Indian Council of Agricultural Research

RESOLUTION

New Delhi-1, the 27th July 1967

No. 8-3/67-A.S.IV.—Shri J. S. Sarma, Economic and Statistical Adviser in the Department of Agriculture is appointed as a member of the National Committee reconstituted to coordinate and review the progress and results of Nationwide Agricultural Demonstrations, vide Resolution No. 8-3/67-A.S.IV, dated the 27th May, 1967, of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED that the resolution may be communicated to all concerned.

B. P. PAL, Additional Secy
& Director General, I.C.A.R.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING*New Delhi, the 26th July 1967***RESOLUTION****SUBJECT.**—*Study Group on Hospitals—Setting up of*

No. F.22-57/64-H.Vol.II.—The Study Group on Hospitals set up under this Ministry Resolution No. 22-57/64-H, dated the 27th August 1966 and extended till 27-5-1967 vide Resolution dated the 21st March, 1967, shall also undertake a review of the working of the Central Government Health Scheme, to evaluate its progress and performance and to make suggestions for improvements and reduction in Government liability. It has, therefore, been decided to extend the period of the Study Group upto the end of December, 1967. Other terms and conditions remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to the Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat/State Government/Union Territories/Ministries/Department of the Government of India/Cabinet Secretariat/The Comptroller and Auditor General of India and members of the Study Group/DGHS (CGHS).

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information

R. N. MADHOK, Jt. Secy.**MINISTRY OF EDUCATION***New Delhi, the 18th July 1967*

No. F. 8-1/66 YS 4—In continuation of the Ministry of Education Notification of even number dated the 18th May, 1967 regarding nominations on the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation.

Shri A. K. Singh,
Principal,
Lakshmi Bai College of Physical Education,
GWALIOR (MADHYA PRADESH).

is nominated an *ex-officio* member of the Central Advisory Board of Physical Education & Recreation with immediate effect and up to the 27th August, 1968 *vice* Dr. P. M. Joseph.

R. L. ANAND, Under Secy.**MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING****(Transport Wing)***New Delhi, the 28th July, 1967***RESOLUTION**

No. 28-MT(5)/67—In pursuance of the Government of India, late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) Resolution No. 24-MT(6)/52 dated the 17th August, 1959, as amended from time to time, the Central Government reconstituted the Merchant Navy Training Board for a period of two years *w.e.f.* the 22nd July, 1965. On the expiry of the life of that Board on 22-7-67, the Central Government is pleased to reconstitute the Merchant Navy Training Board for a period of two years *w.e.f.* the 1st August, 1967 and to appoint the following persons on the Board—

President

Minister of Transport and Shipping

Chairman

Director General of Shipping.

Vice-Chairman

Additional Director General of Shipping

Members

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Transport and Shipping, dealing with the Merchant Navy Training Institutions. | <i>Ex-Officio</i> |
| 2. Deputy Financial Adviser, Ministry of Finance dealing with the Ministry of Transport and Shipping. | |
| 3. Nautical Adviser to the Govt. of India | Do |

- | | |
|--|--|
| 4. Chief Surveyor with the Government of India. | <i>Ex Officio</i> |
| 5. Principal, Lal Bahadur Shastri Nautical and Engineering College, Bombay. | Do. |
| 6. Capt. Supdt. Training Ship 'Dufferin', Bombay | Do |
| 7. Director, Marine Engineering Training, Calcutta | Do |
| 8. Capt. N. K. Kershaw, Capt. Supdt Training Ship 'Mekhala', Vishakhapatnam. | Do |
| 9. Shri R. S. Arumugam | Member, Lok-Sabha. |
| 10. Shri Muhammad Ishaque | Member, Rajya-Sabha. |
| 11. Shri A. B. Chandramani, Joint Educational Adviser (Technical), Ministry of Education, New Delhi. | Representative of the Ministry, of Education. |
| 12. Capt. Kirpal Singh, I.N. Director of Personnel Services, Naval Headquarters. | Representative of the Ministry of Defence. |
| 13. Prof. P. J. Madan, Pro-Vice-Chancellor, M.S. University, Baroda. | Representative of All India Council for Technical Education. |
| 14. Shri C. P. Srivastava | Representative of the Shipping Corporation of India. |
| 15. Shri T. M. Gokuldas } | Representatives of Indian National Steamship Owners' Association. |
| 16. Shri A. Mukherji } | |
| 17. Director, Marine Deptt., Calcutta Port Commissioners, Calcutta. | Representative of the Port Trusts. |
| 18. Capt. D. Houghton Capt. A. B. McSweeney, (alternate member in the event of the Board's Meeting in Calcutta.) | Representatives of Calcutta Liner Conference (Crews) and the Owners/Agents Committee (Crews) Bombay. |
| 19. Capt. H. S. Maini | Representative of the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, New Delhi. |
| 20. Shri J. D. Randeni | Representative of Maritime Union of India. |
| 21. Shri Leo Barnes | Representative of the National Union of Seafarers of India. |

The Principal, Lal Bahadur Shastri Nautical and Engineering College, Bombay, will act as Member-Secretary of the Board.

ORDER }

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, all the Ministries of the Govt. of India, all the State Governments, the Port Trusts and the Director General of Shipping, Bombay.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. MADAPPA, Joint Secy.**MINISTRY OF RAILWAY****(Railway Board)***New Delhi-1, the 27th July 1967*

No. E(GR)I-66RR2-1.—In the Ministry of Railways (Railway Board) Notification No. E(GR)I-66RR2-1, dated

18-2-1967 published in Part I, Section I of the Gazette of India dated 18-2-1967, the following corrections are made :—

- (1) Delete the letters "S.E.D." appearing in line 3 below column 2 against Railway Department in item (iii) of para 5(b) on page 179.
- (2) Read "Schedule to Appendix I" for "Schedule to Appendix" appearing in the heading of the Schedule on page 184, Col. 1.
- (3) The last 5 lines of "item (c) Reinforced concrete" under heading "4. Structural Design" appearing on page 185, Col. 1, viz., "Design of simple cantilever and counterfort retaining walls. Equivalent moments of inertia for reinforced concrete sections.

Theory of elastic deflections and outline of investigation of stresses in re-inforced concrete arches" shall be deleted.

- (4) Read "vitrolite" for "virolite" in page 186, col. 2, under heading "10 BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES" below the sub-heading "(i) BUILDING MATERIALS" in item "Glass and plastics," line 3.
- (5) Read "quadruple" for "quadrup" on page 189, col. 1, under heading "15. ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING", below sub-heading "A-TELEGRAPHY" in item "3. Multiplex Telegraphy", line 3.
- (6) Read "termination" and "exemption" for the words "terminate" and "examination", respectively, appearing on page 196, Col. 2, sub-para 2 of item (3) of para 1 giving the particulars of the Indian Railway Service of Engineers etc., line 4.
- (7) Read "Indian Railway Stores Service" for the words "Stores Department of Indian Railways", appearing in page 197, Col. 1, item (7) of para 1 giving the particulars of Indian Railway Service of Engineers etc., lines 7 and 8.
- (8) Read "Indian Railway Service of Mechanical Engineers", "Indian Railway Service of Signal Engineers" and "Indian Railway Service of Electrical Engineers" for the words "Mechanical Engineering and Transportation (Power) Department", "Signal Engineering Department" and "Electrical Engineering Department", respectively appearing in page 197, Col. 1, item (9) of Para 1 giving particulars of the Indian Railway Service of Engineers, etc., lines 8, 9, 11 and 12.
- (9) Read "Rs. 1800-100-2000-125-2250" for "Rs. 1800-100-2000" appearing in page 198, Col. 2, item (d) of para 5 giving the particulars of Telegraph Engineering Service, Class I, against Senior Administrative Grade.

No. F67CO1/66/RBI.—In partial modification of the Ministry of Railways (Railway Board) Notification No. E67 CO1/66/RBI dated 3-7-1967 the Government of India have decided to appoint Shri T. S. Parthasarathy, Chief Commercial Supt. Northern Railway now appointed as Officer on Special Duty, Railway Board, as Member Secretary of the "Railway Catering and Passenger Amenities Committee 1967", in place of Shri K. N. Krishnan, Director, Rail-Coordination, Railway Board.

C.S. PARAMESWARAN, Secy. Rly. Board

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 17th July 1967

No. EL-II-24(2)/67.—The Ministry of Irrigation and Power had sponsored in 1966 an investigation to be carried out by the experts of National Rural Electric Co-operative Association in U.S.A. on the feasibility of initiating Rural Electric Co-operatives in India with the assistance of the USAID with a view to expanding the pace of rural electrification. A team of experts had accordingly come to India and after detailed site investigation and study of the schemes submitted by the interested States, the team has submitted a report on Phase-I of the work which has been accepted, in principle, by the Government of India. One of the recommendations of this Report (Phase I) is that the Government of India should establish an *ad-hoc* Committee or panel.

2. Pursuant to this recommendation made by the team and *ad-hoc* Committee has been set up. The composition and functions of the *ad-hoc* Committee would be as follows:

Composition

Chairman

- 1 Secretary, Ministry of Irrigation and Power.

Members

- 2 Commissioner (Co-operation), Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Deptt. of Cooperation).
- 3 Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure—Plan Finance Division).
- 4 Chief (Power), Planning Commission.
- 5 Commissioner, Industrial Cooperatives, Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development).
- 6 Shri V. Kurien, General Manager, Kalra District Cooperative Milk Producers' Union Ltd., Anand.

Functions

The functions of the Committee will be as follows :—

- (i) to co-ordinate matters in the various interested Government Departments;
- (ii) to arrange for necessary capital funds; and
- (iii) to give guidance and directions to the programme and generally assist in getting the Pilot Projects started.

3 The following officers are also appointed to serve as Secretary and Joint Secretary to the aforesaid Committee and to provide liaison with the Pilot Projects and other concerned authorities.

- (1) Shri H. K. Bansal, Director, Planning and Progress Directorate, C.W. & P.C. (P.W.)....Secretary and
- (ii) Shri H. Prasad, Under Secretary, Department of Cooperation Ministry of Food, Agriculture, CD and Cooperation.....Joint Secretary.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to the Members concerned the State Governments, the State Electricity Boards, the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India

K. P. MATHRANI, Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Deptt. of Labour and Employment)

New Delhi, the 1st August 1967

No. L&P 4/1/36/66.—In pursuance of Rule 3(a) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education the Government of India hereby nominates Dr. S. T. Merani, Joint Secretary, Ministry of Labour & Employment as Chairman of the said Board with effect from the 31st July, 1967, *vice* Shri P. M. Nayak, Additional Secretary, Ministry of Labour & Employment, who is going abroad on deputation.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P. 4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I Section I dated December 20, 1958/ Agrahavana 29, 1880, as amended from time to time :—

"J. Shri P. M. Nayak,

Additional Secretary,

Ministry of Labour & Employment

New Delhi.

Nominated by the Govt of India."

The following shall be substituted :—

"1. Dr. S. T. Merani,

Joint Secretary,
Ministry of Labour & Employment

New Delhi.

Nominated by the Govt. of India"

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi-1, the 28th July 1967

No. 258/4/67-AVD.—It has been decided by the Government of India that in Ministry of Home Affairs Resolution No. 242/110/65-AVD.II, dated the 7th November 1966, regarding Police Research Advisory Council, after clause (f) to Note 3 under paragraph 2, the following clause shall be inserted, namely:

“(g) Representatives of the Indian Conference of Social Work, or any recognised research unit, or technical experts or specialists concerned with any field of police research.”

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories, all Ministries of the Government of India etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. MUKHERJEE, Jt. Secy.

RULES

New Delhi, the 12th August 1967

No. 6/24/67-CS(I).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in February, 1968 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information:—

- (i) Central Secretariat Service—Assistants' Grade;
- (ii) Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B);
- (iii) Railway Board Secretariat Service—Grade IV (Assistants);
- (iv) Posts of Assistant in certain Departments, Offices of the Central Government not included within the purview of the Central Secretariat Service/Indian Foreign Service (B)/Railway Board Secretariat Service.

A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/Posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to compete for. Candidates are warned that they will not be considered for appointment to any Service/post not specified by them.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to compete. No request for alternation in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 30th April, 1968.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either:—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Sikkim, or
- (c) a subject of Nepal, or
- (d) a subject of Bhutan, or
- (e) Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of

India and if he belongs to category (f) the certificate of eligibility will be issued for a period of one year after which such a candidate will be retained in service subject to his having acquired Indian citizenship.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories:—

- (i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.
- (ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.
- (iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then without a break. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B).

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5(a). A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st January, 1968 i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1944 and not later than 1st January, 1948.

Provided that a candidate who was born earlier than 2nd January, 1944 but not earlier than 2nd August, 1943 shall also be eligible for admission to the examination as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1968 only.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable:—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;
- (iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;
- (v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November

ber, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

- (vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);
- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in disturbed areas, and released as a consequence thereof;
- (xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in disturbed areas, and released as a consequence thereof, who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and
- (xii) up to a maximum of three years, if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must hold a degree of any of the universities enumerated in Appendix I, or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not the above qualification, as educationally qualified provided that he has passed an examination, conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—Candidates who are otherwise eligible but who have taken degrees from foreign universities which are not included in Appendix I may also apply and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that

there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

(c) Women candidates who are married will not ordinarily be eligible for appointment to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S.(B). A woman member of this Grade who is not married shall obtain the permission of the Government, in writing, before her marriage is solemnised. At any time, after the marriage a woman member of the Service may be required to resign from the service, if the Government is satisfied that her family and domestic commitments are likely to come in the way of the due and efficient discharge of her duties as a member of the Service.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

10. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission

to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination :

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service/post, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be in that Service/post.

NOTE.—Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application (c.f. Col. 26 of the application form) but a candidate may be assigned to any Service/post for which the examination is held.

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

20. Candidates will be required to pass a test in type-writing conducted by the Commission, at a minimum speed of 30 words per minute, within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

21. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, the Railway Board Secretariat Service the Indian Foreign Service (B), the posts of Assistants in the Election Commission of India and the Department of Tourism, are briefly stated in Appendix III.

MANGLI PRASAD, Dy. Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India.
(vide Rule 6)

Indian Universities

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the university Grants Commission Act, 1956.

Universities in Burma

The University of Rangoon.
The University of Mandalay.

English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading Sheffield and Wales.

Scottish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

Irish Universities

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Dublin. The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab, The Dacca University, The University of Sind, The Rajshahi University.

University in Nepal

The Tribhuvan University, Kathmandu

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (vide Rule 6).

1. Alankar of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Banaras.
3. French Examination "Baccalaureat".
4. French Examination "Propedeutique".
5. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
6. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.
7. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.
8. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Technical Education.
9. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
10. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, Provided that the Course has been successfully completed as a "full" student.

APPENDIX II

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

	Max. Marks	Time Allowed.
1. Essay	100	2 hours
2. General English	200	3 hours
3. Arithmetic	100	2 hours
4. General Knowledge including Geography of India.	100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer paper 1 and paper 4 either in Hindi or in English. Paper 2 and paper 3 must be answered in English by all candidates.

Note 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

Note 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi should indicate their intention to do so in col. 7 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects at the examination.

6. Marks will not be allotted for more superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of Coins, Weights and Measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of Coins, Weights and Measures may be set

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

1. *Essay*.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

2. *General English* :

- (i) *Precis writing and drafting* : Questions to test the understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary or precis. Candi-

- dates will also be required to wraft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.
- (ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.
- (iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms, etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language.

3. Arithmetic :

Ratio and proportion, percentage, average graphical representation of data, reading of linear graphs and tabulation of data.

The question will be designed to test intelligence, accuracy and rapidity in working.

4. General Knowledge including Geography of India :

Knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on Indian History of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

1. (i) CENTRAL SECRETARIAT SERVICE.

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

- (1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) = Rs. 1,100-50-1,300-50-1,600-100-1,800.
- (2) Grade I (Under Secretary or equivalent) = Rs. 900-50-1,250.
- (3) Section Officers' Grade = Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.
- (4) Assistants' Grade = Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Person appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(ii) RAILWAY BOARD SECRETARIAT SERVICE.

(a) The service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as recruitment, training, promotion etc. are concerned, are regulated by the Railway Board's Secretariat Service Scheme, which is similar to the Central Secretariat Service Scheme.

(b) The Railway Board Secretariat Service consists of the following grades :—

- (i) Assistant Director/Under Secretary = Rs. 900-50-1,250.
- (ii) Section Officer = Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.
- (iii) Assistants = Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(c) Officers recruited direct as Assistants will be on probation for two years during which they will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test will result in the discharge of the probationer from service.

(d) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(g) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

- (i) will be eligible for pensionary benefits; and
- (ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join Service.

(h) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(i) As regards leave and other conditions of service staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway Officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) INDIAN FOREIGN SERVICE (B).

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :—

Grade	Designation	Scale of Pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad.	Rs. 900-50-1250
Integrated Grade II & III.	Attaches and Section Officers at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-80-EB-30-830-35-900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions/Posts abroad.	Rs. 210-10-270-15-30-EB-15-450-EB-20-530.

Note 1.—Direct Recruitment is made to the integrated Grades II and III and to Grade IV. Assistants promoted to the integrated Grade II and III are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

NOTE 2.—In accordance with the rules and orders in force from time to time, Grade I officials may be promoted to the Senior Scale of the Indian Foreign Service carrying a scale of pay Rs. 900-50-1,000-60-1,600-50-1,800.

2. Candidates selected for Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S. (B) will be appointed against permanent and long-term temporary vacancies. Appointments will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission, subject to the rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad, candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service, and the Railway Board Secretariat Service. Further, all such persons will be liable to serve in any post either in India or abroad, to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families, etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All officers appointed to the I.F.S. (B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S. (B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

(2) ELECTION COMMISSION, INDIA.

The posts of Assistants in the Election Commission carry a scale of pay of Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530 like the posts of Assistants in the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the Central Secretariat Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

2. The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. The next two higher grades are—

(1) Section Officers' Grade—Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.

(2) Under Secretaries' Grade—Rs. 900-50-1,250.

(3) DEPARTMENT OF TOURISM.

The posts of Assistants in the Department of Tourism carry a scale of pay of Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530 as prescribed for Grade IV of the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the C.S.S. Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to the posts included in the cadre of the C.S.S.

The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government from time to time. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in the discharge of the probationer from service.

On completion of the probation, the Government may confirm the probationer in his appointment, or if his work or conduct, has, in the opinion of the Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as the Government may consider necessary.

Assistants will be eligible for promotion to higher grade of Assistant Director (Administration) in the pay scale of Rs. 400-25-500-30-590-EB-30-800 in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

